जनपद बिजनौर में रोजगार की स्थिति का विष्लेशणात्मक अध्ययन

प्राप्तिः 26.02.2021
स्वीकृतः 15.03.2021

डॉ0 वन्दना राजपूत
अर्थशास्त्र विभाग
आर.एस.एम. कॉलेज, धामपुर (बिजनौर)
Email: vandanarajput659@gmail.com

डॉ0 एस.के. राजपूत
अर्थशास्त्र विभाग
आर.एस.एम. कॉलेज, धामपुर (बिजनौर)

सारांश

भारत में स्वतन्त्रता के उपरान्त रोजगार की समस्या सदैव बनी रही है। यद्यपि 1951 से प्रारम्भ विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार वृद्धि के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं तथापि यह समस्या निरन्तर बढ़ती रही है। आज भी चुनाव का मुख्य मुद्दा रोजगार की समस्या ही बना हुआ है अतः शोधार्थिनी द्वारा अपने इस शोध पत्र में जनपद बिजनौर की स्थिति का विश्लेषण कर इस समस्या को दूर करने हेतु सुझावों को संकलित किया गया है।

प्रस्तावना

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत में ग्रामीण समाज का महत्व बहुत बढ़ गया है। क्योंकि सरकारों का गठन वोट बैंक द्वारा होता है। ग्रामीण विकास को ध्यान में रखकर ही पंचवर्षीय योजनाएं व नीतिगत कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये है जिनका उद्देश्य रोजगार उत्पन्न करके आर्थिक विषमता को कम करना है।

शोध पत्र के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य जनपद बिजनौर की राजनैतिक परिधि में रोजगार स्तर की स्थिति का मूल्यांकन करना है तथा रोजगार में वृद्धि हेतु सुझावों को संकलित करना है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध पत्र उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल के जनपद बिजनौर की राजनैतिक सीमाओं तक सीमित है। अतः समंकों का संकलन जनपद बिजनौर से सम्बन्धित पत्र–पत्रिकाओं से किया गया है। मेरा यह शोध पत्र मुख्य रूप से द्वितीयक समंकों पर आधारित है। समंकों का विश्लेषण करने हेतु वर्गीकरण, सारणीयन, निर्देशांक तकनीक इत्यादि का प्रयोग किया गया है।

समंकों का सांख्यिकीय विश्लेषण

प्रस्तुत शोध पत्र में रोजगार सम्बन्धी समंकों का विश्लेषण निम्नांकित तालिकाओं में दर्शाया गया है।

तालिका–1 : कषशि एवं कषशि पर आधारित उद्योगों में रोजगार की स्थिति

जनगणना वर्ष	कर्मकर संख्या				
	कृषक **(i)**	कृषि–श्रमिक **(ii)**	पारिवारिक उद्योग **(iii)**	अन्य उद्योग **(iv)**	योग
1961	176135 (100)	36521 (100)	53154 (100)	123431 (100)	389241 (100)
1971	191136 (108.5)	97220 (266.2)	29405 (55.3)	101288 (82.1)	419049 (107.7)
1981	226822 (128.8)	125668 (344.1)	44303 (83.3)	148558 (120.4)	545351 (140.1)
1991	246035 (139.1)	201658 (552.2)	26092 (49.1)	222317 (180.1)	696102 (178.8)
2001	231684 (131.5)	170740 (467.5)	37455 (70.5)	256223 (207.6)	884481 (227.2)

स्रोत–सांख्यिकी पत्रिका जनपद बिजनौर 1990 व 2010 (............) स्थिर आधार सूचकांक

तालिका संख्या–1 में जनगणना वर्ष 1961 से 2001 तक कृषि व कृषि पर आधारित उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की प्रगति को दर्शाया गया है। प्रगति की गणना हेतु शोधार्थिनी ने 1961 को आधार मानकर स्थिर आधार सूचकांक ज्ञात किये हैं।

उपरोक्त समंकों से स्पष्ट है कि पारिवारिक उद्योगों में उच्चावन की स्थिति प्रदर्शित होती है जबकि कृषि आधार अन्य उद्योगों जैसे– मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन, डेयरी, काष्ठ उद्योग इत्यादि के रोजगारों में निरन्तर वृद्धि प्रगति के प्रतीक है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पारिवारिक उद्योगों के पतन के कारण इन उद्योगों में रोजगार के अवसर कम हुए हैं जबकि अन्य सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

तालिका संख्या–2 : विभिन्न क्षेत्रों में पुरुष एवं महिला रोजगारों की स्थिति

रोजगार का क्षेत्र	रोजगारों की संख्या (जनगणना–2001)		
	पुरुष	महिला	योग
सार्वजनिक क्षेत्र	21818 (88.1)	2936(11.9)	24754 (100)
केन्द्रीय सरकार	930(97.7)	22(2.3)	952 (100)
राज्य सरकार	9850(91.0)	969(9.0)	10819(100)
अर्द्ध केन्द्रीय सरकार	1402(95.1)	72(4.9)	1474(100)
अर्द्ध राज्य सरकार	7656(82.5)	1625(17.5)	9281(100)
स्थानीय निकाय	2020(89.1)	248(10.9)	2268(100)
अन्य	7550(93.0)	572(7.0)	8122(100)
कुल	51226(88.81)	6444(11.21)	57670(100)

स्रोत– सांख्यिकी पत्रिका 2010 संख्या एवं अर्थविभाग बिजनौर, (.....) – स्थिर आधार सूचकांक

तालिका संख्या 2 में जनपद बिजनौर के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुश एवं महिला रोजगारों की स्थिति को दर्शाया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद में 57670 कर्मचारियों में 51226 पुरुष कर्मचारी (88.80प्रतिशत) तथा 6444 महिला कर्मचारी (11.2 प्रतिशत) कार्यरत थे। उपसमंकों के आधार पर स्पष्ट है कि जनपद बिजनौर में पुरुष कर्मचारियों के रोजगार स्तर की तुलना में महिला कर्मचारियों का रोजगार स्तर बहुत ही निम्न स्तरीय है।

तालिका संख्या 3 : जनपद में कार्यनुसार रोजगारों की स्थिति

वर्ष	निर्माण कार्य	व्यापार एवं वाणिज्य	यातायात संग्रहण एवं संचार	अन्य कर्मकर	कुल कर्मकर
1961	4767 (100)	16914 (100)	5130 (100)	71490 (100)	98328 (100)
1971	6619 (138.8)	20171 (119.0)	9426 (183.7)	36422 (50.9)	72638 (73.8)
1981	11134 (233.5)	28415 (167.7)	12580 (245.2)	39462 (55.2)	91591 (93.1)
1991	18046 (378.5)	47707 (281.6)	15823 (308.4)	62101 (86.8)	143677 (146.1)
2001	20595 (432.0)	58706 (346.5)	17563 (342.3)	85352 (119.3)	182216 (185.3)

स्रोत– सांख्यिकी पत्रिका 2010, संख्या एवं अर्थविभाग बिजनौर, (.....) स्थिर आधार सूचकांक

तालिका में जनगणना वर्श 1961 से 2001 तक जनपद बिजनौर में कार्यनुसार रोजगारों की स्थिति को दर्शाया गया है। 1971 वे 1981 को छोड़कर शेष जनगणना वर्षो में रोजगार स्तर में वृद्धि हुई है।

तालिका संख्या 4 उ.प्र. राज्य जनपद में कार्यरत चीनी मिलों में रोजगारों की स्थिति

	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
2005–06	410 (100)	1015 (100)	225 (100)	510 (100)	2160 (100)	3510 (100)	2795 (100)	5035 (100)
2006–07	358 (87.3)	920 (90.6)	200 (88.8)	480 (94.1)	2120 (98.1)	3438 (97.9)	2678 (95.8)	4838 (96.1)
2007–08	340 (82.9)	890 (87.7)	190 (84.4)	440 (86.3)	2080 (96.3)	3410 (97.2)	2610 (93.4)	4740 (94.1)
2008–09	338 (82.4)	890 (87.7)	170 (75.6)	410 (80.3)	2040 (94.4)	3390 (96.6)	2548 (91.2)	4690 (93.1)
2009–10	333 (80.5)	855 (84.2)	160 (71.1)	380 (74.5)	1920 (88.8)	3382 (96.4)	2413 (86.3)	4617 (91.7)

स्रोत – चीनी मिलों का रिकार्ड (....) स्थिर आधार सूचकांक

तालिका–4 में जनपद बिजनौर में उ0प्र0 राज्य निगम की दो इकाईयां, सहकारी क्षेत्र की एक इकाई तथा निजी क्षेत्र की 8 इकाईयों में कार्यरत स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों की प्रगति को वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–10 तक दर्शाया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि जनपद बिजनौर में विगत पांच वर्षो में चीनी मिलों में रोजगार स्तर गिरा है। इसका मुख्य कारण नवीन तकनीकी को अपनाया जाना है।

तालिका संख्या 5 –जनपद में कार्यरत पेपर मिलों में रोजगार की स्थिति

वर्ष	रोजगारों की संख्या		योग (इ)
	स्थायी ()	अस्थायी (इ)	
2005–06	700 (100)	1152 (100)	1852 (100)
2006–07	720 (102.9)	1200 (104.2)	1920 (103.7)
2007–08	735 (105.0)	1369 (118.8)	2104 (113.6)
2008–09	735 (105.0)	1397 (121.7)	2132 (115.1)
2009–10	737 (105.3)	1419 (123.2)	2156 (116.4)

स्रोत – पेपर मिलों के अभिलेख

तालिका 5 में जनपद बिजनौर में कार्यरत चार पेपर मिलों में रोजगार स्तर की स्थिति को दर्षाया गया है जो पेपर मिलों में रोजगार स्तर में निरन्तर वषद्धि के द्योतक है।

तालिका संख्या – 6 :

जनपद में स्थापित शासकीय एवं अर्द्धशासकीय शिक्षण संस्थाओं में रोजगार की स्थिति

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय(शासकीय)			उच्च प्राथमिक विद्यालय (अशासकीय)			माध्यमिक विद्यालय शासकीय एवं अर्द्धशासकीय			महाविद्यालय शासकीय एवं अर्द्धशासकीय			योग
	स्त्रियां	पुरुष	कुल	स्त्रियां	पुरुष	कुल	स्त्रियां	पुरुष	कुल	स्त्रियां	पुरुष	कुल	
2002–03	1859 (100)	3892 (100)	5751 (100)	487 (100)	1212 (100)	1699 (100)	503 (100)	1892 (100)	2395 (100)	56 (100)	109 (100)	165 (100)	10010 (100)
2003–04	3974 (213.7)	4328 (111.2)	8302 (144.3)	839 (172.3)	1740 (143.5)	2579 (151.7)	513 (101.9)	1929 (101.9)	2442 (101.9)	58 (103.5)	109 (100)	167 (101.2)	13490 (134.7)
2004–05	3988 (214.5)	4346 (111.6)	8334 (144.9)	923 (189.5)	1793 (147.9)	2716 (159.8)	516 (102.5)	1940 (102.5)	2456 (102.5)	59 (105.3)	112 (102.7)	171 (103.6)	13677 (136.6)
2005–06	4469 (240.3)	5457 (140.2)	9926 (172.5)	1277 (267.2)	195 (161.1)	3230 (190.1)	531 (105.5)	1948 (102.9)	2479 (103.5)	61 (108.9)	114 (104.5)	175 (106.1)	15810 (157.9)
2006–07	4630 (249.0)	5720 (146.9)	10350 (179.9)	1511 (310.2)	2104 (173.5)	3615 (212.7)	545 (108.3)	1953 (103.2)	2498 (104.3)	57 (101.8)	119 (109.2)	176 (106.7)	16739 (165.2)
2007–08	4820 (259.2)	5882 (151.1)	10702 (186.0)	1884 (386.8)	2496 (205.9)	4380 (257.7)	554 (110.1)	1978 (104.5)	2532 (105.7)	121 (216.0)	143 (131.1)	264 (160)	17878 (178.6)
2008–09	6131 (329.8)	5856 (150.4)	11987 (208.4)	2088 (428.7)	2676 (220.7)	4764 (280.4)	563 (111.9)	2013 (106.3)	2567 (107.1)	126 (225)	246 (225.6)	372 (225.4)	19690 (196.7)
2009–10	6186 (332.7)	5887 (151.2)	12073 (209.9)	2158 (443.1)	2670 (220.2)	4828 (284.1)	601 (119.4)	2161 (114.2)	2762 (115.3)	131 (233.9)	157 (144)	288 (174.5)	19951 (199.3)

स्रोत – सांख्यिकी पत्रिका जनपद बिजनौर (......) – स्थिर आधार सूचकांक

तालिका 6 में जनपद में स्थापित शासकीय एवं अर्द्धशासकीय शिक्षण संस्थाओं में रोजगार की स्थिति को दर्षाया गया है। जनपद में लगभग 23 उच्च शैक्षणिक संस्थान, अनेकों माध्यमिक विद्यालय तथा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ भारी संख्या में रोजगार प्रदान कर रहे हैं।

जनपद में रोतगार सम्बन्धित समस्यायें

जनपद में रोजगार को बढ़ावा देने व बेरोजगारी को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनायें चलायी जा रही हैं और इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बहुत मोटी धनराशि भी इन योजनाओं पर व्यय की जा रही है किन्तु फिर भी रोजगार सम्बन्धित समस्यायें उत्पन्न होती जा रही हैं जैसे –

1. ग्रामीणों को कार्यक्रमों की पूरी जानकारी न दिया जाना।
2. योजनाओं का स्वरूप व्यावहारिक न होना।
3. ग्रामों में गुटबंदी व जातिवाद का फायदा।
4. शिक्षा की कमी
5. घूसखोरी
6. योजनाओं के संचालन में राजनैतिक हस्तक्षेप इत्यादि।

समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

जनपद बिजनौर में रोजगार स्तर में वृद्धि हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक योजनओं का क्रियान्वयन किया है–

अपने अध्ययन के दौरान यह पाया कि इन योजनाओं से कुछ सीमा तक रोजगार में वृद्धि हुई है तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कम हुआ है। परन्तु इन योजनाओं को जितनी सफलता प्राप्त करनी चाहिये थी, वह प्राप्त नहीं हो सकी है। अतः मेरे द्वारा कुछ सुझाव संकलित किये गये हैं जिनके द्वारा इन योजनओं के सम्मुख आने वाली बाधाओं को दूर करके इनकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है, मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं

1. वर्तमान में संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से करें और इन योजनाओं में आने वाली कठिनाईयों का समाधान करें।
2. जनपद में रोजगार उपलब्ध कराने व उत्पादिता का स्तर ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में सुझाव है कि उत्पादन की नीतियों में नये विकास केन्द्रों जैसे–दुग्धशालायें, पशुपालन, मुर्गीपालन, मछलीपालन लघु स्तर के उद्योगों इत्यादि में विनियोग किया जा सके।
3. रोजगार में वृद्धि हेतु मनरेगा योजना के तहत सरकार को इस योजना को कृषकों से लिंक करना चाहिये जिसके लिए वह कृषक के साथ उसके कृषि कार्यो में सहयोग करें तथा कृषक से एक उचित मजदूरी के साथ–साथ आर्थिक सहायता के रूप में सरकार से धन प्राप्त करे।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव है। अतः सरकार द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी के लिए शिक्षित–प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा उचित जानकारी दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा प्रदत्त रोजगार योजनाओं का संचालन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसका लाभ वास्तविक व्यक्तियों को उपलब्ध हो। इसी के साथ–साथ कृषि कार्य में मनरेगा का सहयोग करके कृषकों की मजदूरों सम्बन्धी समस्या का निराकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर भी रोजगारों में वृद्धि की जा सकती है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना(2008) : भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2002) : भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. Datt, Ruddar, Sundharam , K.P.M(2006) : *Indian Economy,* S. Chand & Company Ltd. Ramnagar, New Delhi
4- *The journal of Rural and Agricultural Research Gramin Vikas Siksha Prasar Samiti,* MIG-81, Rishi Marg, New Shahganj, Agra- 282010 U.P.
5. *कुरूक्षेत्र,* वर्ष 54, फरवरी 2008, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
6. *योजना,* जून 2008 से मार्च 2011 तक, 538, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।